# स्वदेशी जागरण मंच

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–110022
दूरभाषः 011–26184595, Web-swadeshionline.in

*प्रेस विज्ञप्ति*

## गैर लोक तात्रिक एवं गुपचुप तरीके से किये जा रहे यूरोपीय समुदाय–भारत का मुक्त व्यापार समझौते के विरोध में धरना एवं प्रदर्शन 22 मार्च 2011 के अवसर पर जारी

भारत सरकार विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 2007 से प्रारंभ यूरोपीय समुदाय और भारत सरकार के बीच चल रही समझौते की वार्ता अब अपने अंतिम चरण पर है। मीड़िया से आ रही खबरों के आधार पर ऐसा लगता है कि भारत सरकार यूरोपीय समुदाय के साथ समझौते पर कुछ ही दिनों में हस्ताक्षर करने वाली है।

यूरोपीय समुदाय के साथ किये जा रहे मुक्त व्यापार समझौते विश्व व्यापार संगठन में दी गयी बाध्यताओं के प्रावधानों से भी कहीं आगे बढ़कर हैं। इन समझौतों में यूरोपीय समुदाय द्वारा दी जा रही सब्सिड़ी और गैर टेरिफ प्रतिबंधों को मान्य करते हुए अपने देश में उन देशों से आने वाली 90 प्रतिशत वस्तुओं के आयातों पर टेरिफ समाप्त करने, संवेदनशील सेवा क्षेत्र जैसे बैंकिग और वित्त, खुदरा व्यापार, ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य इत्यादि में विदेशी निवेश को अनुमति देने, ट्रिप्स समझौते से भी आगे बढ़ते हुए डाटा एक्सक्लूसिविटी, पेटेंट अवधि में वृद्धि इत्यादि सहित कई प्रावधान रखे गए है। जिन सिंगापुर मुद्दों को विश्व व्यापार संगठन से बाहर रखने हेतु भारत ने अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर संघर्ष किया था, उन्हें भी अब निवेश, सरकारी खरीद और प्रतियोगिता नीति संबंधी अध्यायों के अंतर्गत इन मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल किया जा रहा है।

ये सभी प्रावधान हमारे विकास पर भारी असर डाल सकते है, क्योंकि इनके द्वारा किसानों, मछवारों, डेरी और पशु–पालक, कृषि आधारित उद्योग और बड़े उद्योगों (केवल कुछ को छोड़कर) और खुदरा एवं निर्माण जैसी सेवाओं के बाजार और आमजन की रोजी–रोटी पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। कुछ शिक्षित लोगों के लिए चाहे सीमित मात्रा में कुछ नौकरियां अवश्य सृजित हो सकती है लेकिन इससे हमारे बहुसंख्यक अकुशल मजदूरों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता। राजस्व की हानि भी एक महत्वपूर्ण विषय है। बैंकिंग क्षेत्र को विदेशी

कपंनियों के लिए खोलने से सर्वजन को उधार मिलने में कठिनाई होगी और साथ ही साथ हाल ही में आए वित्तीय संकट आने पर कोई समाधान भी नहीं होगा।

ट्रिप्स से आगे बढ़ते हुए दी जा रही बाध्यताओं से भारत के द्वारा सस्ती दवाएं बनाने की क्षमता पर तो असर पड़ेगा ही इसके साथ ही साथ भारत के आम आदमी की ही नहीं बल्कि समस्त विकासशील विश्व के नागरिकों की पहुंच से दवाईयां बहुत दूर हो जायेगी। 'इन्वेस्टर टू स्टेट' सरीखे प्रावधानों के द्वारा विदेशी निवेशकों को दिए जा रहे संरक्षण से समाज कल्याण उद्देश्य से भविष्य में कानून बनाना सरकार के लिए असंभव हो जायेगा। सरकारी खरीद को विदेशी कंपनियों द्वारा बनाये गए उत्पादों पर भी समान रूप से लागू करने के प्रावधानों से अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों जैसे लघु उद्योगों, महिलाओं, पिछड़ी जातियों इत्यादि के लाभ के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले नीतिगत उपायों को छोड़ना पड़ेगा।

इस प्रकार के गैर लौकतांत्रिक और गुपचुप तरीके से भारत–यूरोपीय समुदाय मुक्त व्यापार समझौते सहित विभिन्न समझौतों पर बातचीत और हस्ताक्षर के संबंध में चल रही प्रक्रिया पर हम अपनी गंभीर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से पारदर्शिता का स्पष्ट अभाव है। देश के आर्थिक और सामाजिक ढ़ांचे पर ये समझौते भारी रूप से प्रभाव डालने वाले है। राज सरकारों, अन्य प्रभावित क्षेत्रों के साथ बातचीत और संसद में पूरी चर्चा के बिना इन समझौतों को अंजाम दिया जा रहा है। देश के विकास के प्ररिप्रेक्ष्य में मुक्त व्यापार समझौतों पर व्यापार नीति के संबंध में देश की संसद और राज्य विधान सभाओं में अवश्य चर्चा होनी चाहिए। समझौतों के प्रारूप और उसके प्रभाव का विश्लेषण इन मंचों पर अवश्य रखाा जाना चाहिए, ताकि वे जन प्रतिनिधियों के द्वारा पढ़ा और विश्लेषित किया जा सके। इससे पहले कि इन समझौतों पर हस्ताक्षर हो इनकी संसदीय चर्चा कराई जाए।

हम सरकार से मांग करते है कि वह अपनी व्यापार नीति को अधिक पारदर्शी, लोक तांत्रिक एवं सहभागितापूर्ण बनाए। गुपचुप तरीके से चल रहे यूरोपीय समुदाय–भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर तुरंत रोक लगाई जाए।